

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 12/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/46

प्रार्थी:-

गुणेशराम पुत्र उम्मेदराम जाति देवासी
निवासी चांदपोल गेट के अन्दर,
सोजत सिटी तहसील सोजत जिला
पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण:-

1. मृतक देवाराम पुत्र राजूराम के
विधिक वारिसान
1/1 लक्ष्मण पुत्र स्व. देवाराम
1/2 मोहनलाल पुत्र स्व. देवाराम
1/3 रामलाल पुत्र स्व. देवाराम
2. सुन्दरी देवी पत्नी मोहनलाल जाति
प्रजापत निवासी कुम्हारों का बास,
नयापुरा सोजत सिटी तहसील
सोजत जिला पाली राजस्थान।
3. ग्राम पंचायत रेन्दड़ी जरिये सरपंच
पंचायत समिति सोजत तहसील
सोजत जिला पाली राजस्थान।
4. ग्राम विकास अधिकारी, पदेन
सचिव, ग्राम पंचायत रेन्दड़ी,
पंचायत समिति सोजत, तहसील
सोजत जिला पाली राजस्थान।

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल सिंह।

—: निर्णय :-

दिनांक : 28/01/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 44/1982-83, दिनांक 13.07.1982 संकल्प संख्या 13 दिनांक 05.02.1984 एवं उसकी पालना में देवाराम पुत्र राजूराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 161 दिनांक 06.02.1984 के विरुद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1/1 से लगाय 1/4, 3 व 4 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बासनी मुथा में खसरा संख्या 38 एवं खसरा संख्या 37 की भूमि को सम्मिलित करते हुये ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसके पड़ोस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में मंगलाराम राईका का जाव, उत्तर दिशा में सुखीया बावरी की भूमि, दक्षिण दिशा में रास्ता, दरवाजा एवं



गुणेशराम देवासी का जाव स्थित है। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, उससे परे जाकर ग्राम पंचायत ने खातेदारी कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। आवेदनकर्ता ने न तो प्रस्तावित भूमि का नक्शा पेश किया, न ही पड़ोस अंकित किये, न आपत्ति इशतिहार जारी किया, न ही बयान लिये गये और न ही मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है, जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय सोजत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में डिक्री पारित हुई है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिनुसार आबादी भूमि में प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार आवेदन पेश किया, जिस पर भूमि का नक्शा तैयार कर पंचों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर पूरी प्रक्रिया अपनाते हुये पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1984 में जारी किया गया है और प्रार्थी ने 40 वर्ष की देरीना जैर निगरानी याचिका पेश की है, जो कि म्याद बाहर है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 44/1982-83, दिनांक 13.07.1982 संकल्प संख्या 13 दिनांक 05.02.1984 एवं उसकी पालना में देवाराम पुत्र राजुराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 161 दिनांक 06.02.1984 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 40 वर्ष बाद पश्चात् पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की, इसके अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of



130

cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brought to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the revisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते हैं। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 40 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

अधिवक्ता अप्रार्थी का अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय, सोजत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में डिक्री जारी हो चुकी है इसलिये जैर निगरानी याचिका के जरिये प्रश्नगत पट्टे को निरस्त नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टे के विरुद्ध पेश की गई है, जिसका श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 Uma Soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता



140

न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित होने से अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 256 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ नक्शा तैयार करने के व्यय पेटे दो रूपये की राशि जमा करानी होगी। इसके पश्चात नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जायेगा एवं नियम 258 के तहत मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा पंचों द्वारा "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 259 के तहत अस्थायी निर्णय करने एवं नियम 260 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 260 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 261 के तहत प्रदत्त हैं। नियम 262 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान है एवं नियम 264 के तहत नीलामी की प्रक्रिया उल्लेखित है व नियम 265 के तहत किये गये नीलाम की पुष्टि के प्रावधान है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण एवं भूमियों का निःशुल्क आवंटन के प्रावधान नियम 267 में उल्लेखित है। नियम 268 के तहत हस्तान्तरण तथा आवंटन अनुमोदनाधीन एवं आबादी का विक्रय से अपवर्जन के प्रावधान नियम 269 में प्रदत्त है। किसी आबादी भूमि का नियम 263 के तहत भुगतान कर दिया जाने, नियम 265 नीलामी की पुष्टि करने और नियम 270 के अधीन कोई अपील नहीं होने की स्थिति में नियम 271 के तहत विक्रय-विलेख जारी किये जाने का प्रावधान है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने की आधिकारिता का प्रश्नगत है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारित रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाते है कि ग्राम पंचायत से मिसल संख्या 44/1982-83 के अनवान पर देवाराम पुत्र राजूजी राईका बासनी मुथा के नाम से दर्ज केवल सरबरक प्राप्त हुआ है जिस पर सरबरक, आज्ञा सूची, रिपोर्ट, नक्शा, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, आपत्ति नोटिस, गवाहान, फैसला अंकित है परन्तु मिसल में ऐसे कोई दस्तावेज संलग्न न होकर किसी अन्य व्यक्ति कुनाराम पुत्र मदुराम जाट के पक्ष में जारी मिसल की आदेशिका व आवेदन पत्र शामिल है। इससे यह स्पष्ट होता है कि



24

ग्राम पंचायत ने बिना कोई मिसल कायम किये केवल सरबरक के आधार पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है अर्थात् उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व न तो आवेदन पेश किया गया, न निर्धारित राशि जमा करवाई गई, न नक्शा तैयार किया गया, न मौका निरीक्षण किया गया, न आपत्ति नोटिस प्रकाशित किया गया और न ही गवाहों के बयान लिये गये। उक्त सरबरक में अंकित प्रविष्टियों के समर्थन में कोई मूल दस्तावेज, अभिलेख मिसल में उपलब्ध नहीं है यानि सरबरक में केवल औपचारिक रूप से प्रविष्टियों का अंकन किया गया है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसके अतिरिक्त अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961-नियम 255 से 265-आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है-प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई-भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई-कोई आपत्तियाँ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है-विक्रय को अभिखण्डित किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157-पंचायती राज अधिनियम, 1994-धारा 63 व 97-आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की-जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता-प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती-नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं-अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।



Handwritten signature

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 44/1982-83, दिनांक 13.07.1982 संकल्प संख्या 13 दिनांक 05.02.1984 एवं उसकी पालना में देवाराम पुत्र राजुराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 161 दिनांक 06.02.1984 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली